www.ccsuniversity.ac.in

प्रायोगिक समाचार पत्र

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

परिसर

(अक्टूबर 2021 विशेषांक)

आत्मनिर्भर बने बिजली में, पानी का संचयन भी..... 2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु..... 4

विश्वविद्यालय ने कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए खोली 7

निराशा को दूर कर देती है विवेकानंद 6

कुलपति जी की कलम से

कोरोना रूपी महा त्रासदी से संपूर्ण विश्व मानवता उभरकर नवसृजन पथ पर पुनश्च अग्रसर हुई है। इस महा त्रासदी ने संपूर्ण विश्व को आभासी पटल पर निर्भर बनाया और विगत लगभग डेढ़ वर्ष में सामाजिक एवं शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन करते हुए व्यक्ति आभासी दुनिया का अभ्यस्त सा होने लगा। सकारात्मक सोच, अपनी जिजीविषा एवं नवोन्मेष को संकल्पित मानव ने इस आपदा को अवसर के रूप में परिवर्तित किया है। केंद्र एवं प्रदेश शासन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देश एवं सबका साथ - सबका विकास - सबका- विश्वास के सिद्धांत ने सरकार के कार्यो, नीतियों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है, जिस कारण भी यह संभव हो पाया है। हम सभी क्रमशः इस त्रासद परिस्थिति से उभरने की ओर अग्रसर हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव में उल्लास एवं उत्साह से परिपूरित हो नवरंग एवं नवसृजन को उन्मत्त हैं।

आपदा के इस दौर में विश्वविद्यालय ने अपने शिक्षार्थियों के बहुआयामी व्यक्तित्व विकास एवं उन्नयन हेतु आभासी मंच एवं अन्य माध्यमों से विविध आयोजन कर कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हमने अपने विश्वविद्यालय में लागू कर दिया है, जिससे शिक्षार्थियों को नए अवसर प्रदान होंगे। विविध नवोन्मेषी प्रयासों के माध्यम से हमने आपदा को अवसर में बदलने का सार्थक प्रयास भी किया है। पल्लव सदृश्य हमारे नवागंतुक शिक्षार्थी विश्वविद्यालय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने को उपलब्ध हैं। आपदा काल से निकलकर हम सभी नव उल्लास के साथ नवसृजन की ओर अग्रसर हों, ऐसी मेरी मंगलकामना है.....

- प्रो नरेंद्र कुमार तनेजा, कुलपति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति करेगी भारत को जाग्रत: मा. कुलाधिपति

नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद के विचारों को समाहित कर देश के सम्मुख उपस्थित हुई : मा. आनंदीबेन पटेल

परिसर संवाददाता

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज्य में शिक्षा के मुद्दे को पूरी गंभीरता से रेखांकित कर अंग्रेजी शिक्षा और सभ्यता को भारत के लिए विनाशकारी बताया था। देश का दुर्भाग्य यह था कि 1947 के बाद सत्ता जिनके हाथों में आई थे, वे स्वयं गांधी जी के हिन्द स्वाराज्य को काल बाहय अभिलेख मानते थे। इसलिए भारत कहीं नेपध्य में चला गया और इंडिया मंचीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक हो गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मात्र शिक्षा का अभिलेख नहीं है बल्कि भारत के चित को प्रतिस्थापित कर विराट को जाग्रत करने का साधन है। सीसीएसयू के दीक्षांत समारोह में

कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्र-छात्राओं को ऑनलाइन संबोधित करते हुए यह बात कही।

कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 स्वामी विवेकानंद के विचारों को समाहित करके देश के सम्मुख उपस्थित हुई है। यह भारत की श्रेष्ठता को भी व्यवहार में लाकर भारत को विश्वगुरू के सिंहासन पर प्रतिस्थापित करने के लिए कटिबद्ध है।

विवि की भूमिका को सराहा

कुलाधिपति ने सीसीएसयू से संबद्ध 10 कॉलेजों को मॉडल या नोडल सेंटर के रूप में स्थापित करने की प्रशंसा की। कुलाधिपति ने कोरोना काल में प्रतिदिन चार हजार भोजन पैकेट उपलब्ध कराने, ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और पोर्टल पर ई-कंटेंट उपलब्ध कराने में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भूमिका की सराहना की। कुलाधिपति ने कहा कि विश्वविद्यालय तकनीक से छात्रों को शेष दुनिया से जोड़ते हैं।

विवि की पहल

छात्रों के लिए सुनहरा अवसर.....

शुरू हुए अनेक रोजगारपरक और स्किल आधारित पाठ्यक्रम

परिसर संवाददाता

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बदलते समय के साथ निरंतर स्वयं को बदल रहा है। छात्रों के सामने भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए विश्वविद्यालय में अनेक नए पाठ्यक्रम शुरू किये गए हैं।

विश्वविद्यालय परिसर में पिछले पांच वर्षो में रोजगार परक, स्किल आधारित तथा गुणवत्तापरक शोध को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक नए पाठयक्रम संचालित किए गए हैं। इन पाठयक्रमों की भौतिक आवश्यकताओं को देखते हुए नए भवनों का भी निर्माण किया गया है। साथ ही केंद्रीय मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिका के रखरखाव हेतु आधुनिक सुविधाओं से एक केंद्रीय मूल्यांकन भवन का निर्माण भी किया गया है। जिसका उदघाटन माननीय कुलाधिपति एव श्री राज्यपाल शीध्र ही विश्वविद्यालय आकर करेंगी।

पत्रकारिता विभाग में चार नए कोर्स

इसी सत्र से

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पत्रकारिता और जनसंचार विभाग इसी सत्र (2021-2022) से चार नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और रोजगारपरक तथा कौशल विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने यह पहल की है।

पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पत्रकारिता में रोज बदलते आयामों को ध्यान में रखते हुए विभाग में चार डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जनसंपर्क एवं विज्ञापन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), फिल्म प्रोडक्शन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), डिप्लोमा इन फंगशनल जर्नलिज्म (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), एवं मोबाइल पत्रकारिता (छह माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम) इस वर्ष शैक्षिक सत्र 2021-22 से शुरू हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग पहली बार ऐसे कोर्स शुरू कर रहा है। अभी तक छात्रों को इन कोर्स को करने के लिए मेरठ से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वे मेरठ में रहकर ही इन कोर्स को कर सकते हैं। इन कोर्स के लिये जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है।

नए पाठयक्रम एक नजर में

- ❑ वाणिज्य विभाग में
  - बी.कॉम आनर्स
  - एम. कॉम
- ❑ संस्कृत विभाग में
  - योग
  - ज्योतिष एवं कर्मकांड
- ❑ इंस्टीटयूट ऑफ बिजनेस स्टडीज में
  - पीएच.डी.
  - बीबीए
  - बीबीए एचए
  - एमबीए एचए
- ❑ सर छोटूराम इंस्टीटयूट ऑफ (इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी में
  - बीएससी (कंप्यूटर साइंस)
- ❑ हिन्दी विभाग में
  - बीए
- ❑ ललित कला विभाग में
  - एम.ए. (एप्लाइड आटर्स)
- ❑ पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में
  - बीजेएमसी
  - एम.फिल
  - पीएच.डी.
  - पीजी डिप्लोमा इन जनसंपर्क एवं विज्ञापन
  - पीजी डिप्लोमा इन फिल्म प्रोडक्शन
  - पीजी डिप्लोमा इन फंग्शनल जर्नलिज्म
  - सर्टिफिकेट इन मोबाइल जर्नलिज्म
- ❑ विधि अध्ययन संस्थान में
  - पीएच.डी.

महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति : कुलपति

परिसर संवाददाता

मेरठ। महिलाओं का सम्मान भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है अबला नारी शब्द हमारी शब्दावली में ही नहीं है यदि हमारी शब्दावली में अबला नारी शब्द होता प्राचीन व वैदिक काल में और स्वाधीनता से पूर्व रानी लक्ष्मीबाई सहित अनेक वीरांगना कैसे होती महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए यह बात चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने महिला अध्ययन केंद्र व महिला हेल्थ क्लब के शुभारंभ के अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि हेल्थ क्लब से बालिकाओं के स्वास्थ्य के साथ मानसिक वह बौद्धिक स्तर भी बढ़ेगा वही महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण स्थान पा सकेंगी। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में 50% आबादी महिलाओं की है जो सामाजिक दूरियों को तोड़ते हुए सांस्कृतिक विशेषता को प्रस्तुत कर रही हैं आज हर क्षेत्र में हर फील्ड में वह बराबर की भागीदारी दे रही हैं हमको अपनी सोच को बदलना होगा और महिलाओं को आदर देखकर सम्मानित करना होगा। यह अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला ने कहा कि केवल उच्च पदों पर बैठना ही महिला सशक्तिकरण नहीं है बल्कि उनका सम्मान उनको बराबर की हिस्सेदारी देना महिला सशक्तिकरण आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर महिलाएं अपना 100% ना दे रही हो बल्कि वह पुरुषों से एक कदम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रो वाई विमला ने भी अपने विचार व्यक्त किये। महिला अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर बिंदु शर्मा ने सभी का स्वागत किया डॉ अनिल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा मंच का संचालन डॉ अलका तिवारी ने किया।

अब कॉलेजों को जंतुओं पर अनुसंधान करना हुआ सरल

- **जंतुओं पर शोध करने के लिए विश्वविद्यालय में खुला विश्व स्तरीय सेंटर**
- **कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने किया एनिमल हाउस का विस्तार**

परिसर संवाददाता

मेरठ। अब कॉलेजों को सरल होगा जंतुओं पर अनुसंधान करना क्योंकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जंतुओं पर शोध करने के लिए अनुसंधान केंद्र यानी एनिमल हाउस का विस्तार हो गया हैं। कॉलेजों के छात्रों को जंतुओं पर अनुसंधान करने के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित एनिमल हाउस में वे शोध कर सकेंगे।

शोध करने के लिए के लिए छात्रों को केवल अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।एनिमल हाउस का विस्तार करते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह काम आने वाले समय में बहुत योगदान देगा शोध करने के लिए छात्र एनिमल हाउस में विश्व स्तरीय शोध कर सकेंगे तथा अपना पेपर पब्लिश करा सकेंगे। जंतु विज्ञान विभाग विभागाध्यक्ष और एनिमल हाउस की संयोजक प्रोफेसर नीलू जैन गुप्ता ने बताया कि एनिमल हाउस एथिकल कमेटी से संबंद्ध है। साथ ही यह मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से भी संबंद्ध है। छात्रों को यहां पर शोध करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके बाद वह जिस भी जंतु पर अपना शोध करना चाहते हैं वह जंतु लाकर शोध कर सकते हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर यह जंतुओं पर शोध करने के लिए पहला प्रयास है जो विश्वविद्यालय से संबंद्ध कॉलेजों में जंतुओं पर शोध करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।

इस दौरान प्रोफेसर संजय भारद्वाज प्रोफेसर एके चौबे प्रोफेसर बिंदु शर्मा रमेश यादव आदि मौजूद रहे।

- विद्युत उत्पादन के लिए विश्वविद्यालय में स्थापित सोलर प्लांट।

विद्युत आपूर्ति में विश्वविद्यालय आत्मनिर्भरता की ओर

- **खपत प्रतिमाह 1400 किलोवॉट, बनाते हैं 1260 किलोवॉट**
- **विश्वविद्यालय के 18 भवनों पर लगाये गये हैं सोलर पैनल**

परिसर संवाददाता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पूरी तरह चरितार्थ किया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बिजली में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। विश्वविद्यालय ने परिसर के 18 भवनों पर सोलर प्लांट लगा रखे हैं। इन प्लांटों से 1260 किलोवॉट बिजली बनती है। विश्वविद्यालय की खपत 1400 किलोवॉट है। केलव 140 किलोवॉट बिजली का भुगतान विश्वविद्यालय को करना पड़ता है।

2013 में लगाया प्लांट

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 2013 से सोलर प्लांट लगने की शुरुआत हुई। शुरूआत में केवल एक या दो भवनों पर ये प्लांट लगाये गये थे। लेकिन धीरे-धीरे परिसर के 18 भवनों पर यह व्यवस्था कर दी गई। इससे हर माह 1260 किलोवॉट बिजली पैदा होती है। इसका उपयोग विश्वविद्यालय में किया जाता है।

हर साल बच जाते है करोडों रुपये

सोलर प्लांट लगने से विश्वविद्यालय को हर साल करोडों रुपये की बजत होती है। सोलर प्लांट लगने से पहले विश्वविद्यालय बिजली के बिल का भुगतान करोड़ों रुपये में करना पड़ता था। सोलर प्लांट लगने से बिजली का बिल आधे से भी कम हो गया है।

होता है रखरखाव

यदि सोलर पैनल का रखरखाव ना किया जाये तो उस पर धूल मिट्टी जम जाती है। इसके कारण सोलर पैनल के माध्यम से बनने वाली बिजली की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन विश्वविद्यालय में इनका रखरखाव भलीभांति किया जाता है। हर तीसरे दिन सभी पैनल की सफाई की जाती है।

पानी की बचत के लिये लगे 40 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

- **हर साल 10 फीट ऊपर आ जाता है पानी का स्तर**
- **चार साल से विश्वविद्याललय में नहीं किया गया कोई बोरिंग**

धरती में पानी का स्तर दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार को नए बोरिंग करने पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। लेकिन चौधरी चरण विश्वविद्यालय में इसके उलट हो रहा है। यहां पानी का स्तर बढाने के लिए रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये गये हैं। यही नहीं इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नियमित साफ-सफाई भी की जाती है। इस प्रयास का असर यह हुआ है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बीते चार साल में तीस से चालीस फीट तक पानी का स्तर बढ गया है।

परिसर में लगे है 40 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

हर साल बारिश का लाखों लीटर पानी यूं ही बह जाता है, लेकिन परिसर में बरसात का पानी संचित करने के लिए 40 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये गये हैं। इसका असर यह हुआ है कि परिसर में पानी का स्तर हर वर्ष दस से पंद्रह फीट तक ऊपर आ जाता है।

हर साल बोरिंग में बढ़ाना पड़ता था 10 फीट पाइप

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था से पहले हर स्थान की तरह विश्वविद्यालय परिसर में भी पानी का स्तर गिरता जा रहा था। यदि कोई नया बोरिंग होता तो करीब तीन सौ फीट तक बोरिंग करना पड़ता था, तब जाकर पानी आता था। हर साल विश्वविद्यालय को प्रत्येक बोरिंग पर दस फीट तक पाइप और जोड़ना पड़ता था। लेकिन बीते चार साल में विश्वविद्यालय परिसर में तीस से चालीस फीट पानी का स्तर बढ़ गया है। अब न तो पाइप जोडना पड़ता है और न ही तीन सौ फीट तक बोरिंग करना पड़ता है।

- संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, समन्वयकों और निदेशकों की बैठक में मौजूद कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा।

अनाथ बच्चों के लिए राहत कोष का फैसला, पुरातन छात्र परिषद भी बनेगी

परिसर संवाददाता

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में संकायाध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, समन्वयकों और निदेशकों की एक बैठक का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा ने इसकी अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में फैसला लिया गया कि अनाथ बच्चों के लिए एक रिलीफ फंड बनेगा। इसमें शिक्षकों द्वारा धन एकत्र किया जाएगा। इस फंड से कैंपस में पढ़ने वाले ऐसे बच्चों की मदद की जाएगी जिनके परिजनों की कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो गई और जिनके पास आय का अन्य कोई साधन नहीं है। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी ने पहल करते हुए इस फंड में 50 हजार रुपये की सहयोग राशि प्रदान की।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक विभाग में एक पुरातन छात्र परिषद का गठन किया जाएगा तथा उसका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। पुरातन छात्र परिषद में छात्रों को भी शामिल किया जाएगा।

एक अन्य फैसले के तहत विश्वविद्यालय के हर विभाग द्वारा एक गांव गोद लिया जाएगा। गोद लिए गांव में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जाएगा।

विभागों द्वारा छात्रों और उनके परिजनों को भी वैक्सीन के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही उनसे गूगल फार्म के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाएगी कि परिवार में कितने सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली है। हर सप्ताह उसकी रिपोर्ट भी बनाई जाएगी।

कुलपति द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में अपनी एक्यूआर रिपोर्ट आईक्यूएसी विभाग में जमा करें। विभागाध्यक्षों को ई-मेल के माध्यम से सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिये भी कहा गया।

बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला, कुलसचिव धीरेंद्र वर्मा, कुलानुशासक प्रोफेसर बीरपाल सिंह, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह, प्रो. पवन कुमार शर्मा, प्रो. नवीन चंद्र लोहानी, प्रो. मृदुल कुमार गुप्ता, प्रो. जितेंद्र ढाका, प्रो. वाई सिंह, प्रो. रूप नारायण, प्रो. नीलू जैन, प्रो. स्नेहलता जायसवाल, प्रो. बिंदु शर्मा, प्रो. एसएस गौरव, प्रो शैलेंद्र शर्मा, प्रो विजय मलिक, प्रो. विजय जायसवाल, डॉ. मनोज श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

वित्त समिति की बैठक में बड़े फैसले

परिसर संवाददाता

मेरठ। विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

- बैठक में विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित संस्कृत के सभी पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय परिसर स्थित नियमित पाठ्यक्रमों के समान किए जाने का निर्णय लिया गया।
- बैठक में संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए दो लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया।
- महिला अध्ययन केंद्र के लिए विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने के वास्ते पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया।
- शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए टीचिंग असिस्टेंट रखने के लिए 15 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया।
- दिव्यांग कल्याण के संबंध में गतिविधियां संचालित करने के लिए पांच लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया।
- चेक की जगह ई-पेमेंट व्यवस्था लागू करने का निर्णय भी लिया गया।

छात्रों को मुफ्त मिलेगी डिग्री

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि 2017 और उसके बाद के वर्षों की डिग्रियां छात्रों को मुफ्त दी जाएंगी। विश्वविद्यालय में अभी तक 2017 के बाद की डिग्री के लिये 250 रुपये शुल्क जमा करना पड़ता था। यह शुल्क परीक्षा फार्म भरने के साथ लिया जाता था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय में 2017, 2018, 2019 और 2020 की करीब 53 हजार डिग्रियां हैं। ये डिग्रियां अब छात्रों को मुफ्त दी जाएंगी। जल्द ही विश्विद्यालय की वेबसाइट पर गूगल फार्म का लिंक दिया जायेगा। इसमें छात्र विवरण भरेंगे। इसके बाद छात्रों के पते पर डिग्री निःशुल्क भेज दी जाएगी।

बताते चलें कि प्रदेश की श्री राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की मा0 कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने पिछले दिनों निर्देश दिया था कि लंबित पड़ी पुरानी डिग्रियों को भविष्य में दीक्षा समारोह के बाद छात्रों को वितरित किया जाए और उनसे उपाधि शुल्क भी न लिया जाए। साथ ही डिग्री वितरण में अदेयता प्रमाणपत्र देना भी जरूर न किया जाए।

विश्वविद्यालय में इस सत्र से एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स

एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स अभी तक यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों में चल रहे थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय इस सत्र से एनसीसी सर्टिफिकेट कोर्स कैंपस में भी शुरू करने जा रहा है। 71 यूपी एनसीसी बटालियन ने 54 सीटों पर प्रवेश की अनुमति प्रदान की है। विश्वविद्यालय ने भौतिक विभाग के सहायक आचार्य, डॉ० अनिल कुमार यादव को एनसीसी का केयर टेकर नियुक्त किया है।

पत्रकारिता विभाग में चार नए कोर्स इसी सत्र से

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और रोजगारपरक तथा कौशल विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने की पहल

मुस्कान कटारिया

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का पत्रकारिता और जनसंचार विभाग इसी सत्र (2021-2022) से चार नए कोर्स शुरू करने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और रोजगारपरक तथा कौशल विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने यह पहल की है।

पत्रकारिता और जनसंचार विभाग के निदेशक प्रोफेसर प्रशांत कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पत्रकारिता में रोज बदलते आयामों को ध्यान में रखते हुए विभाग में चार डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जनसंपर्क एवं विज्ञापन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), फिल्म प्रोडक्शन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), पीजी डिप्लोमा इन फंगशनल जर्नलिज्म (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा), एवं मोबाइल पत्रकारिता (छह माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम) इस वर्ष शैक्षिक सत्र 2021-22 से शुरू हो चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग पहली बार ऐसे कोर्स शुरू कर रहा है। अभी तक छात्रों को इन कोर्स को करने के लिए मेरठ से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वे मेरठ में रहकर ही इन कोर्स को कर सकते हैं। इन कोर्स के लिये जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।

कॉलेजों की संबद्धता बढ़ा

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्याय के कुलपति प्रोफेसर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा की अध्यक्षता में अगस्त 2021 के अंत में हुई कार्य परिषद की बैठक में कई निर्णय लिये गये।

विश्वविद्याय के प्रेस प्रवक्ता के अनुसार समस्त महाविद्यालय और संस्थान जिनकी संबद्धता 25 जून को समाप्त हो गई थी, उनकी संबद्धता 30 नवंबर तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बीएड संस्थानों की संबद्धता भी 30 नवंबर तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे वर्ष 2021-22 के लिए प्रवेश किए जा सकें। ललित कला विभाग में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए अप्लाइड आर्ट 2 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्य परिषद की बैठक में प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार वर्मा, डॉ. दर्शन लाल अरोड़ा, डॉ. अरुण सिंह, डॉ. हरी बाबू खंडेकर, प्रोफेसर अनिल मलिक, प्रोफेसर विजय जायसवाल, प्रोफेसर आनंद कुमार, डॉ. प्रदीप चौधरी, डॉ. जीनत जैदी, डॉ. अंजू सिंह, डॉ. स्मृति दानी, डॉ. दीपशिखा शर्मा, प्रोफेसर प्रशांत कुमार एवं प्रेस प्रवक्ता मितेंद्र कुमार गुप्ता मौजूद रहे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रोजगारपरक एवं कौशल विकास से संबंधित पाठ्यक्रमों के संचालन की नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में चार नए पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस विभाग में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करेंगे तथा देश के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

❐ माननीय कुलपति, प्रोफेसर एन.के. तनेजा

माननीय कुलपति जी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में उ.प्र. के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान पर है। विभाग में संचालित चारों कोर्स निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इन पाठयक्रमों में रोजगार की सम्भावनाएं भी अधिक है। हम प्रवेशित सभी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट कौशल प्रशिक्षण देते हुए उनके करियर को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे।

❐ प्रो. प्रशांत कुमार, निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग

नए कोर्स

- ❐ जनसंपर्क एवं विज्ञापन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
- ❐ फिल्म प्रोडक्शन (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
- ❐ डिप्लोमा इन फंगशनल जर्नलिज्म (एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा)
- ❐ मोबाइल पत्रकारिता (छह माह का प्रमाणपत्र पाठयक्रम)

रोजगार की भाषा बने मातृभाषा

पिछले दिनों देश के कई शैक्षणिक व अन्य प्रतिष्ठानों में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी को प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियां चलाई गई । ऐसे में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे भाषाई आयोजन मात्र एक रस्म अदायगी वाले औपचारिक समारोह बनकर न रह जाएं। देश में हिंदी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर रूप से अभियान जारी रहे। यह सही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता स्वीकार की गई है। उसमें उल्लेख है कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम भारतीय भाषाओं में ही तैयार किए जाएं। यह एक बड़ी चुनौती है जिससे शिक्षाविदों और भाषाविदों के व्यापक सहयोग से ही पार पाया जा सकता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने के पीछे मंशा भी यही है कि शिक्षा ही मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने का आधार होती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति नागरिकों को मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए उनके शारीरिक बौद्धिक और नैतिक विकास के साथ ही राष्ट्र की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान का भाव स्थापित करते हुए देश की एकता और अखंडता का मार्ग प्रशस्त और सशक्त करती है। मातृभाषा में पाठ्यक्रम तैयार करने के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक सोच है। यह विद्यार्थी को उस पाठ्यक्रम से जोड़ती है जिसमें उससे कौशल की अपेक्षा की जाती है न कि भाषाई दक्षता से।

यह भी एक तथ्य है कि जब पाठ्यक्रम मातृभाषा से इतर भाषा में तैयार होंगे तो विषय पर विशेषज्ञता के स्थान पर भाषा के अवबोध पर ही विद्यार्थी का ध्यान बंटेगा। यह कौशल विकास की राह में व्यवधान होगा। वैसे संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं किंतु उसे किसी प्रकार के श्रेष्ठता बोध से न जोड़ा जाए। श्रेष्ठताबोध की भावना से मुक्ति पाने में सबसे बड़ा अवरोध भारतीयों का वह तबका है जो इसे अभिजात्य वर्ग से जोड़ता है और अपनी ही भाषा को लेकर हीनता की ग्रंथि पाले रहता है।

विश्व के सभी विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र अपनी भाषा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वहां स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान,कानून अथवा तकनीक सब उनकी अपनी मातृभाषा में उपलब्ध है। ऐसे में शिक्षा बच्चों पर कोई अनावश्यक दबाव नहीं जानती बल्कि अपनी सुगमता से अवधारणात्मक स्तर पर विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। विकसित देशों में नागरिकों द्वारा अपनी मातृभाषा में परस्पर सहज संवाद के अतिरिक्त अपनी भाषा में ही तमाम वैज्ञानिक, दार्शनिक, समाजशास्त्रीय रचनाओं तथा नवीन सिद्धांतों का उसी भाषा में निरूपण करने का कार्य बहुत सहायता से किया जाता रहा है।

फ्रांस, नीदरलैंड्स, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और इजराइल आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यह देश अपनी मातृभाषा में पूर्ण गौरव भावना के साथ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता स्वीकार की गई है। यह नीति कौशल विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र अपनी भाषा में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।

- प्रोफेसर प्रशांत कुमार
निदेशक, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

कार्य कर विश्व के सामने एक प्रतिमान रखते हैं। यह इसलिए भी उल्लेखनीय है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक रहे एपीजे अब्दुल कलाम अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता इसलिए प्राप्त कर सके क्योंकि उन्होंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी। मातृभाषा में बातों को बहुत सुलभता के साथ समझा और संप्रेषित किया जा सकता है। इसका मनोविज्ञान यह होता है कि हम जिस भाषा में सर्वाधिक सहज होते हैं हमारी चिंतन प्रक्रिया भी उसी भाषा में कार्य कर रही होती है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें अपनी तकनीक को निरंतर बेहतर बनाना होगा, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मातृभाषा रोजगार की भाषा बने। यदि मातृभाषी युवक रोजगार के प्रश्न पर किसी विदेशी भाषा की दुहाई देकर छांट दिए जाएं तो यह अपने आप में त्रासद स्थिति ही कही जाएगी। हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त सभी भाषाएं अपना गौरवशाली इतिहास रखती हैं। साथ ही इन सभी भाषाओं में विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियां यह रेखांकित करती हैं कि मातृभाषा में शिक्षा एक सशक्त भारत और सशक्त भविष्य की आधारशिला बनाती है।

देश में इन दिनों आत्मनिर्भरता की बहुत चर्चा है आत्मनिर्भरता वास्तव में प्रत्येक स्तर पर सोची जाने वाली एक राष्ट्रव्यापी सोच है। इस सोच में देश की समृद्धि और विकास में शामिल हर छोटी बड़ी इकाई का समावेश करना होगा। यदि इसे संभव बनाना है तो उत्पादकता से जुड़े सभी वर्गों के लिए वही भाषा अपनानी होगी जो उन्हें कार्य कुशल निपुण और कामयाब बनाए।

इससे वह अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर पाएंगे। वास्तव में आत्मनिर्भरता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा तभी सहज एवं सरल हो सकती है जब वह मातृभाषा में हो इसे ऐसे समझें कि जब कामगारों और काम कराने वालों की भाषा समान होगी तो उनमें आपस में बेहतर संप्रेषण स्थापित किया जा सकेगा।

हमारे समाज में बहुधा विद्यार्थियों के शैक्षणिक चयन में समाज और परिवार का भारी दबाव होता है। इससे प्रायः विद्यार्थी अपनी इच्छा और अपनी अभिवृत्ति के अनुसार विषयों का चयन नहीं कर पाते जब तक उनमें ऐसे चयन की समझ विकसित होती है तब तक बहुत विलंब हो चुका होता है।

इसी मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के समक्ष यह विकल्प रखा गया है कि यदि वे किसी पाठ्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ कि यह नीति कौशल विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विद्यार्थी जब अपनी अभिवृत्ति और रुचि के अनुसार चयनित विषय में रमता है तो उसमें सहज ही कौशल विकसित हो सकता है।

किसी भी भाषा के विस्तार की निर्भरता उसके प्रयोग पर आधारित होती है। कई जनजातीय भाषाएं केवल प्रयोग न होने के कारण ही विलुप्त हो गईं। भाषा संस्कृति की वाहक होती है। संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहे उसके लिए भाषा का जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख बिंदु

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इससे पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, जिसे 1992 मे संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को शत प्रतिशत लाने का और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

इस नई शिक्षा नीति, 2020 के घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख बिंदु (स्कूली शिक्षा के संदर्भ में)

❐ स्कूली शिक्षा के लिए शैक्षणिक ढांचे और पाठ्यक्रम रूपरेखा एक 5+3+3+4 डिजाइन से होगी। जिसके तहत क्रमशः

- फाउंडेशनल स्टेज : आंगनवाड़ी, प्री-स्कूल के 3 साल .प्राथमिक के 2 साल (कक्षा 1-2) 3 से 8 वर्ष के बच्चों सहित।
- प्रीपरेटरी स्टेज रू 3 साल (कक्षा 3-5) 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित।
- मिडिल स्कूल स्टेज रू 3 साल (कक्षा 6-8) 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित।
- सेकेंड्री स्टेज रू 4 साल (कक्षा 9-12) 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित (2 फेज में, यानी पहले फेज मे कक्षा 9 और 10 और दूसरे फेज में 11 और 12)।

❐ द डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा) पर बुनियादी साक्षरता और संख्या-ज्ञान पर उच्चतर-गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।

❐ विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय मे अध्ययन करने के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय शामिल होंगे।

❐ नई शिक्षा नीति 2020 में त्रि-भाषा फॉर्मूले को लागू किया जाएगा। 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम से कम 3 मे 2 भारतीय भाषाएं हो।

❐ विद्यार्थियों को कम उम्र में 'सही को करने' के महत्व को सिखाया जाएगा और नैतिक निर्णय लेने के लिए एक तार्किक ढाँचा दिया जाएगा।

❐ स्कूल शिक्षा के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पठचर्या रूपरेखा एनसीएफएसई 2020-21 तैयार होगा। इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

❐ प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सभी विद्यार्थियों के स्कूल आधारित आकलन के आधार पर तैयार होने वाले और अभिभावक को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड को पूरी तरह नया रूप दिया जायेगा।

❐ यह प्रगति कार्ड एक समग्र, 360-डिग्री, बहु-आयामी कार्ड होगा जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक, साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किये गए विश्लेषण का विस्तृत विवरण, विद्यार्थियों की विशिष्टताओं समेत दिया जाएगा। इसमें स्व-मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य और खोज-आधारित अध्ययन में प्रदर्शन, क्विज, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि शिक्षक मूल्यांकन सहित शामिल होगा।

हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्नातक स्तर पर वर्तमान सत्र से लागू हो चुकी है। स्नातक स्तर के सभी पाठयक्रमों की बोर्ड ऑफ स्टडीज संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए कॉमन मिनिमम पाठयक्रमों के आधार पर स्नातक स्तर के सभी पाठयक्रम बन चुके हैं तथा 2021-2022 से लागू किये जा रहे हैं।

❐ प्रो0 हरे कृष्णा

❐ शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जो भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए विद्यार्थी आकलन एवं मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशनिर्देश बनाने जैसे मूल उद्देश्यों को पूरा करेगा।

❐ वर्ष 2021 तक एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा, एनसीएफटीई 2021 तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी।

❐ नई शिक्षा नीति, 2020 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों या दिव्यांग बच्चों को किसी भी अन्य बच्चों के समान अवसर प्रदान करने के लिए सक्षम तंत्र बनाने के महत्त्व को भी पहचानती है।

❐ भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों को गुणवत्तपूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर-समावेशी निधि' का गठन करेगी।

❐ हर राज्य जिले को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वह 'बाल भवन' स्थापित करे जहां हर उम्र के बच्चे सप्ताह में एक या अधिक बार जा सकें और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर सकें।

❐ राज्य में अकादमिक मानकों और पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक मामले एससीईआरटी के नेतृत्व में होंगे, जो कि एक संस्थान के रूप में सदृढ़ किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रमुख बिंदु (उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में)

❐ समग्र और बहु-विषयक शिक्षा के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम. आदि के तर्ज पर, मेरू नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयो की स्थापना की जाएगी।

❐ श्रेणीबद्ध मान्यता की एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से, कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जाएगी।

❐ 2030 तक प्रत्येक जिले मे या उसके नजदीक कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान होगा।

❐ संस्थानों को अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुंच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के एवं जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को मुहैया कराने हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा, बशर्ते उन्हें ऐसा करने के लिए मान्यता प्राप्त हो।

❐ नई शिक्षा नीति, 2020 में स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर, व्यावसायिक तथा पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पुरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पुरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री।

❐ भारत को वहनीय लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा।

❐ छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अन्य छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास होगा।।

❐ वर्ष 2025 तक, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50: विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा।

❐ नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत एक आईआईटीआई (Indian Institute of Translation and Interpretation&IITI) की स्थापना की जायेगी।

❐ शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास नए जोश के साथ किये जाएंगे।

❐ शिक्षा के विभिन्न आयामों को बेहतर बनाने के लिए प्रोद्योगिकी के सभी प्रकार के प्रयोग व एकीकरण को समर्थन दिया जाएगा एवं अंगीकृत किया जाएगा, बशर्ते कि वृहद स्तर पर लागू करने से पहले इनका प्रासंगिक संदर्भों में ठोस एवं पारदर्शी ढंग से आंकलन किया गया हो।

❐ स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढांचे डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जाएगी।

संरक्षकः प्रोफेसर एन. के. तनेजा (कुलपति), **मुख्य संपादकः** प्रो. प्रशांत कुमार, **संपादकः** डॉ. मनोज कुमार श्रीवास्तव, **सपादकीय सलाहकार**- लव कुमार सिंह, मितेंद्र गुप्ता, पेज सज्जा और **संपादकीय टीमः** मुस्कान कटारिया (बीजेएमसी पंचम सेमेस्टर), योगेश कुमार, नरेश सोलंकी (एमजेएमसी तृतीय सेमेस्टर) एवं बीजेएमसी तृतीय व पंचम सेमेसटर के छात्र-छात्राएं।

कुलपति को मिली कर्नल की ऑनरेरी रैंक

परिसर संवाददाता

भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा को कर्नल की ऑनरेरी रैंक से सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें नेशनल कैडेट्स कोर (एनसीसी) का कर्नल कमांडेंट भी नियुक्त किया है। यह एक ऐसा सम्मान है जो प्रतिष्ठित और बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

प्रोफेसर तनेजा को मिले इस सम्मान से न केवल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ बल्कि अन्य स्कूलों और कॉलेजों में भी एनसीसी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। एनसीसी से युवा पीढ़ी के भविष्य को एक आकार मिलता है, देश का अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलती है, जिससे आगे जाकर राष्ट्र निर्माण में सहयोग मिलता है।

प्रोफेसर तनेजा को यह सम्मान पिपिंग समारोह के जरिये 11 सितंबर को ब्रिगेडियर अक्षत अरोड़ा, एसएम ग्रुप कैडर मेरठ और कर्नल गुरुसतिन्दर, सीओ 71 यूपी बटालियन एनसीसी की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

- शिक्षक दिवस के मौके पर समारोह में दीप प्रज्वलित करते सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कुलपति प्रो. एन.के. तनेजा।

जो करते हैं बेहतर समाज का निर्माण, उन्हें मिला सम्मान

उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह

परिसर संवाददाता

गुरु ही ज्ञान का संवर्धन करता है और ज्ञान के संवर्जन से ही देश, समाज और दुनिया आगे बढ़ी है, यह बात उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश एवं सीसीएसयू के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान सांसद व मुख्य अतिथि डॉ. राजेंद्र अग्रवाल ने कहीं।

सीसीएसयू स्थित बृहस्पति भवन में आयोजित शिक्षक बृहस्पति भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह के दौरान सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पहली गुरु उसकी मां होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वीसी प्रो. प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने कहा कि शिक्षक वहीं है जो विद्यार्थियों का उतना ही ध्यान रखें, जितना उसके माता-पिता रखते हैं, इसके बाद कुलसचिव धीरेंद्र कुमार वर्मा ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया, कार्यक्रम का संचालन डॉ. अंजली मित्तल ने किया।

छात्र हित : अब घर बैठे हो रहा समस्याओं का समाधान

- मार्कशीट, डिग्री आदि के लिये घर बैठे आवेदन करते हैं छात्र
- उन्हें दूरदराज से आकर परिसर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते

परिसर संवाददाता

मेरठ-सहारनपुर मंडल में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के छात्रों को अब छोटे-छोटे काम के लिए कैंपस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। छात्र घर बैठे ही डिग्री-मार्कशीट सहित अन्य अनेक डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र समस्या निवारण केंद्र और गोपनीय विभाग को भी इस सिस्टम से जोड़ते हुए छात्रों की दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है।

पहले डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री और रिजल्ट पूरा कराने के लिए छात्रों को दूर-दूर से कैंपस पहुंचना पड़ता था। इससे छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ता था। अब छात्रों की समस्या के समाधान के लिए यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है।

इससे अब छात्रों को समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। छात्र घर बैठे ही अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आदि ले सकते हैं और डिग्री व रिजल्ट पूरा करा लेते हैं। वे इन सब कामों के लिए घर बैठे ही आवेदन कर देते हैं।

डिग्री के लिये विशेष परीक्षा का मौका

विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालत स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों में डिग्री पूरी करने के लिये छात्रों को एक मौका दिया गया है।

जिन छात्रों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, लेकिन किसी एक सेमेस्टर के अपूर्ण होने की वजह से डिग्री पूरी नही कर पाए हैं, वे विशेष परीक्षा के लिये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परीक्षा फार्म भर सकते हैं। जिन छात्रों ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दी है, वे इस विशेष परीक्षा के लिये योग्य नहीं माने जायेंगे।

एमबीए करने वाले छात्र-छात्राओं के लिये इस बार इग्नू ने सीधे प्रवेश करने का मौका दिया है। कोविड को देखते हुए इस बार प्रवेश परीक्षा न कराने का फैसला लिया गया है। एमबीए में प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राएं 30 सितंबर से पहले इग्नू के पोर्टल पर जाकर प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं।

जापान में रिसर्च करेंगी आरती

परिसर संवाददाता

आरती

मेरठ। विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग की एमफिल की छात्रा आरती का जापान की प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मेक्स्ट (MEXT) में चयन हुआ हैं। मेकष्ट (जापान का शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तीन साल के लिए विज्ञान ओर इंजीनियरिंग के स्नातक स्कूल, सयातामा विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट पाठ्यक्रम के लिए तीन साल की पूर्णकालिक स्कॉलरशिप प्रदान करता है। मेक्स्ट (MEXT) विश्व में प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति में से एक है, जिसमें स्कॉलरशिप के अंतर्गत टयूशन फीस, परीक्षा फीस, एंट्रेस फीस और आने-जाने का खर्च जापान सरकार द्वारा वहन किया जाता हैं। मेक्स्ट (MEXT) स्कॉलरशिप स्वीकृति दर केवल 0.5 प्रतिशत के साथ सबसे कठिन और प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप में से एक हैं। जापान सरकार द्वारा छात्रा को प्रतिमाह एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि तीन वर्ष तक प्रदान की जायेगी।

आरती का चयन जापान की सायतामा यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सांइस एंड इंजीनियरिंग विभाग के तहत संचालित 'डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल कैमिकल्स प्रोग्राम' में तीन वर्ष के लिए पीएचडी में हुआ हैं। शोध के दौरान छात्रा का मुख्य फोकस आप्टिकल माइक्रोस्कोपी की सहायता से वायु प्रदूषण के कारण रासायनिक कणों का पेड़-पौधो की वृद्वि एवं व्यवहार का अध्यन रहेगा। मुजपफरनगर के गांव जीवना की निवासी आरती ने कड़ी मेहनत व लगन के साथ स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से तथा स्नातकोत्तर व एमफिल, भौतिकी विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से की है। आरती वर्ष 2020 में एम.फिल. में गोल्ड मेडिलिस्ट भी रह चुकी हैं। आरती ने सितंबर 2020 में भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. बीरपाल सिंह के निर्देशन में स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। छात्रा को कुलपति प्रो0 नरेंद्र कुमार तनेजा एवं प्रतिकुलति प्रो. वाई. विमला ने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।

गार्बेज क्लीनिक में हो रहा कूड़े का निस्तारण

- **गार्बेज क्लीनिक में हो जाता है इसका समाधान**
- **कूड़े से बना खाद पौधों में भर देता है नई जान**

222 एकड़ में फैले चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रोजाना निकलने वाला एक चुटकी भी कूड़ा-कचरा बाहर नहीं फेंका जाता है। इस कचरे का निस्तारण कैंपस में मौजूद गार्बेज क्लीनिक में ही कर दिया जाता है। नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए जो कचरा सिरदर्द बना है, उसी कचरे का यहां वैज्ञानिक विधि से निस्तारण करके खाद बना दिया जाता है, जो पौधों में जान भर देता है।

विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग के परिसर में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। पेड़-पौधों की पत्तियों और घरों का कचरा लगभग 4000 किलोग्राम प्रतिदिन निकलता है। नगर निगम विश्वविद्यालय परिसर का कचरा नहीं उठाता था, जिससे परिसर में गंदगी की समस्या रहती थी। इसके निस्तारण के लिए परिसर में 100 मीटर गुणा 50 मीटर क्षेत्रफल में करीब 57 लाख रुपये की लागत से गार्बेज क्लीनिक (कंपोस्टिंग यूनिट) शुरू की गई। इसमें गीले कचरे के निस्तारण के लिए कंपोस्टिंग पिट और सूखे कचरे के लिए रैक बना रखे हैं। नीले और हरे रंग के कूड़ेदान परिसर में रखे हैं। 90 फीसदी लोग गीला और सूखा कचरा अलग-अलग डालते हैं।

गार्बेज क्लीनिक से दो गार्बेज एंबुलेंस (कचरा गाड़ी) परिसर से कचरा एकत्र करती हैं। इसका सेग्रीगेशन किया जाता है। गीले कचरे को कंपोस्टिंग पिट में डालते हैं। यहां पर 10 प्रोसेसर मशीन लगी हैं। केमिकल डालकर वैज्ञानिक विधि से कचरे को खाद में तब्दील किया जाता है। 10 से 15 दिन में कचरे से खाद तैयार हो जाती है। जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। गार्बेज क्लीनिक पर कूड़ा पहुंचते ही उसे पानी से साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो पानी बर्बाद होता है, उसे भी इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। इसके लिए दो प्लांट लगाए गए हैं।उत्तर भारत में विश्वविद्यालय कैंपस में यह पहला सफल प्रयोग है जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हुआ।

निराशा को दूर कर देती है विवेकानंद जी की प्रतिमा

विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही हमें दाहिनी तरफ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा दिखाई देती है। इस प्रतिमा को देखते ही हमें स्वामी विवेकानंद द्वारा दिये गए संदेशों का ध्यान आता है और हमारे मन से निराशा का भाव दूर हो जाता है। उन्होंने कहा था कि जब तक जीना, तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

उन्होंने कहा था कि पढ़ने के लिये जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा- उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते।

स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय ने छात्र-छात्राओं में यही भाव विकसित करने के लिये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा यहां पर लगवाई है।

यह है ज्ञान की कुटिया

तुलसीदास, कबीरदास, संत रविदास, कथा सम्राट प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे संत, साहित्कारों और कवियों को आपन किताबों में तो खूबपढा होगा, लेकिन अगर आप इन साहित्यकारों, संतों और उनकी रचनाओं से साक्षात्कार करने चाहते हैं तो यह अवसर भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध है।

परिसर में प्रवेश करने के बाद जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो कैंटीन के पीछे हरे-भरे पेड़ों और मैदान के बीचों-बीच लकड़ी, लोहे और सीड के साथ एक खूबसूरत स्ट्रक्चर भी दिखता है।

पत्थर की कटिंग और सीढियों के साथ चारों तरफ मैदान में रोशनी भी लगी हुई है। परिसर में पढने वाले छात्र इसे कुटिया के नाम से जानते हैं। इसका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदी साहित्कार कुटीर हैं। जैसा इसका नाम है वैसा ही यह अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है।

साहित्य और संस्कार का संदेश

साहित्यकार कुटिया में जिन संतों, कवियों और साहित्यकारों की पत्थरों की मूर्तियां लगी हुई हैं, उन सभी के साहित्य के सौंदर्य और जीवन से लोग प्रेरणा ले सकते हैं। नई पीढ़ी जिन संस्कारों से दूर हो रही है, युवा जिस तरह से भटकाव और अवसाद में हैं, वे यहां आकर इन साहित्यकारों की मूर्तियां और उनकी रचनाओं से अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर सकते हैं।

आठ प्रतिमाएं कई संदेश

साहित्यकार कुटिया के अंदर आठ संत, कवि और साहित्कारों की मूर्तियों के साथ ही बोर्ड पर कई संदेश भी लिखे हुए हैं। कई महापुरुषों की उक्तियां, दोहे और चौपाई भी लिखी हुई हैं, जो एक समृद्ध साहित्य को महसूस कराते हैं। विश्वविद्यालय में साहित्यकार कुटिया को बनाने के पीछे का उद्देश्य यह था कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं अपने अंदर संवेदना, संवाद को भी व्यावहारिक रूप में लाएं। अपनी साहित्यिक, सांस्कृतिक विरासत को भी महसूस करें। इन मूर्तियों को देखकर उनके विचारों को पढ़कर प्रेरणा लें और जीवन की डगर पर एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ सकें।

1857 की क्रांति की याद दिलाती है शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा

विश्वविद्यालय प्रांगण में लगी महान क्रांतिकारी और शहीद धन सिंह कोतवाल की प्रतिमा हमें 1857 की क्रांति के दिनों में ले जाती है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी और 1857 के महान क्रांतिकारी और शहीद थे। 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद धन सिंह कोतवाल को दिया जाता है। उस दिन मेरठ में धन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था।

धन सिंह उस समय मेरठ की सदर कोतवाली के पुलिस प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में रात के समय में जेल तोड़कर 836 कैदियो को छुड़ाकर जेल को आग लगा दी गई थी। छुड़ाए गए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए थे। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात क्षेत्र में फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया और उन्हें गिरफ्तार करके मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया।

सेवा और जिजीविषा की प्रेरणा देती है राजा महेंद्र प्रताप की प्रतिमा

परिसर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की प्रतिमा भी लगाई गई है। विश्वविद्यालय का मुख्य और विशाल पुस्तकालय भी उन्हीं के नाम पर है। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह (1 दिसम्बर 1886 दृ 29 अप्रैल 1979) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और महान दानवीर थे।

भारत की अनंतिम सरकार के अध्यक्ष थे। यह सरकार प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान बनी थी और भारत के बाहर से संचालित हुई थी। उन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 1940 में जापान में भारतीय कार्यकारी बोर्ड की स्थापना की थी। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मिलकर उन्होने सन 1911 में बाल्कन युद्ध में भी भाग लिया। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्यों के लिए भी उनका स्मरण किया जाता है।

कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए खोली झोली

- कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट भेजने से पहले उनका निरीक्षण करने के लिए मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के शिक्षकगण।

- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में प्रतिदिन 3 हजार लोगों के लिए भोजन के पैकेट बनाए गए।
- विश्वविद्यालय के दो छात्रावासों के मेस में व्यवस्था करके इस अभियान को संचालित किया गया

परिसर संवाददाता

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने कोरोना से प्रभावित और कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल लोगों को खाना उपलब्ध कराने के लिए अपनी झोली खोल दी। इस दौरान हजारों लोगों को रोजाना भोजन उपलब्ध कराया गया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा के निर्देश पर रोजाना भोजन के तीन हजार पैकेट तैयार करके जरूरततमंदों को व कोरोना योद्धाओं को भेजे गये। भोजन के पैकेट बनवाने के लिए दो छात्रावासों के मेस में सारी व्यवस्था की गई। भोजन के 1500 पैकेट दुर्गा भाभी हॉस्टल में और 1500 पैकेट पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्टल में प्रतिदिन बनाए गए। साथ ही प्रशासन को आश्वस्त किया गया कि यदि आवश्यकता हुई तो भोजन के पैकेट की संख्या बढ़ाई जा सकती है। विश्वविद्यालय की तरफ से 50 हजार से ज्यादा भोजन के पैकेट कोरोना से प्रभावित लोगों तक पहुंचा पहुंचाये गए।

कोरोना से प्रभावित और कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल लोगों को भोजन देने की मुहिम को कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने हर कसौटी पर खरा उतारने का प्रयास किया। यही कारण रहा कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में बन रहे भोजन को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ा। भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया। भोजन की व्यवस्था के दौरान जहां दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भोजन की गुणवत्ता को चेक कर रहे थे, कुलपति के आदेश पर विश्वविद्यालय की टीम भी खाने की जांच रही थी। प्रोफेसर पीके शर्मा, प्रो. ए के चौबे, प्रो. रूप नारायण, प्रोफेसर बीरपाल, इंजीनीयर मनीष मिश्र आदि द्वारा परीक्षण करने के पश्चात ही भोजन के पैकेट तैयार किए गए।

हर दिन बदल गया मेन्यू

प्रशासन के आग्रह पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से तैयार कराए जा रहे पौष्टिक भोजन के पैकेट का मेन्यू रोज बदला गया। सुबह का भोजन अलग होता था और शाम के भोजन का मेन्यू अलग होता था। कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने इस दौरान कहा कि उच्च शिक्षा के संस्थान में उच्च स्तर का भोजन ही तैयार होना चाहिए। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया।

फंसे मजदूरों की सुध ली

- विश्वविद्यालय में चल रहा था अनेक भवनों का निर्माण कार्य
- लॉकडाउन में काम बंद हुआ तो कई राज्यों के मजदूर फंस गए
- विश्वविद्यालय ने की मदद, 50 से अधिक परिवारों को सामग्री बांटी

परिसर संवाददाता

कोरोना वायरस से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में यूं तो सारा शहर थम सा गया था। हर जगह काम बंद पड़े हुए थे। कुछ ऐसा ही हाल विश्वविद्यालय में भी था। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आधा दर्जन से अधिक भवनों का निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन कोरोना के चलते मूल्यांकन केंद्र, विष विज्ञान भवन, हिंदी भवन, पत्रकारिता एवं जनसंचार भवन का निर्माण कार्य भी फिलहाल बंद हो गया था। उस निर्माण को पूरा करने के लिए लगे मजदूर भी लॉकडाउन की वजह से यहीं पर फंस गए थे। ऐसे में इनकी मदद के लिये विश्वविद्यालय ने हाथ आगे बढ़ाए।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने विश्वविद्यालय में निर्माण कर रहे श्रमिकों और मजदूरों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। 50 से अधिक परिवारों को कुलपति जी, कुलानुशासक प्रोफेसर बीरपाल सिंह, वित्त नियंत्रक सुशील कुमार गुप्ता, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक डॉ. अश्विनी शर्मा, सहायक कुलानुशासक डॉ. दुष्यंत चैहान, एससीआरआईईटी के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. राजीव सिजेरिया ने खाद्य सामग्री का वितरण किया।

खाद्य सामग्री में मजदूरों को 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, रिफाइंड, स्वच्छता के लिए दो साबुन दिए गये। 50 से अधिक मजदूर परिवार बिहार के मोतीहारी, पटना, वैशाली, मध्य प्रदेश के टीकमगढ और यूपी के प्रतापगढ, आजमगढ आदि जिलों के रहने वाले थे। इस दौरान सभी ने हाथों में ग्लब्स, मास्क पहन रखा था।

कुलपति ने मजदूरों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता रखने के लिए भी प्रेरित किया। साथ ही ठेकेदार को निर्देश दिए कि वह मजदूरों की मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती न करे। मजदूरों को कहा कि किसी प्रकार की आवश्यकता पडने पर तुरंत सूचना करें।

विश्वविद्यालय द्वारा हर प्रकार की मदद करने का आश्वासन दिया गया। कुलपति ने मजदूरों से कहा कि बिना किसी काम के वह बाहर न निकलें। उन्होंने प्रोफेसर बीरपाल सिंह, डॉ. दुष्यंत चौहान को निर्देश दिए कि वे श्रमिक मजदूरों की देखरेख करते रहें।

हेल्पलाइन से बढ़ाया हौसला

परिसर संवाददाता

चौधरी चरण सिंह विश्विद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में हेल्पलाइन का संचालन भी किया गया। इस दौरान कोरोना से प्रभावित मेरठ के लोगों को मानसिक संबल देने का कार्य किया गया।

इससे लोगों को काफी मदद मिली और कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में मानसिक मजबूती का संचार हुआ।

कोरोना आपदा से निपटने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षण संस्थान भी पीछे नहीं रहे। लॉकडाउन के दौरान लोगों को तनाव से बचाने के लिये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने विशेष प्रबंध किए। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा ने लोगों के मानसिक तनाव को दूर करने की जिम्मेदारी मनोविज्ञान विभाग को सौंपी। मनोविज्ञान विभाग ने इसके लिए पांच हेल्पलाइन बनाईं। इन्में विभाग द्वारा पांच शिक्षकों के नंबर जारी किए गए थे। इन नंबरों पर शिक्षक सुबह 9 से 11 तथा दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक उपलब्ध रहे।

विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई पांच हेल्पलाइन पर दो सप्ताह में 109 कॉल आईं। हेल्पलाइन पर लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने अपने को मानसिक रूप से मजबूत बताया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना के खिलाफ चल रही मुहिम में साथ देने की बात कही। साथ ही उन्होंने हेल्पलाइन से लोगों के मदद करने की इस मुहिम की प्रशंसा भी की।

कुलपति ने कहा कि लोगों को मानसिक मजबूती देने के लिए एक अच्छी पहल की गई। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर स्नेहलता जायसवाल ने बताया कि उस दौरान हेल्पलाइन पर रोजाना 8 कॉल आ रही थीं। अधिकांश कॉल परीक्षाओं और उसकी तैयारी से संबंधित थीं। लोगों के बात करके यह भी पता चला कि मेरठ के लोगों मानसिक रूप से काफी मजबूत हैं।

स्वार्थी मत बनो, दूसरों की मदद करो

परिसर संवाददाता

मेरठ। स्वार्थी मत बनो, सपनों को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद करो। यह आपके सम्मान, निष्ठा और सहयोग में सहायक होगा।

विद्यार्थी किताबें पढें, खुद को अपडेट रखें, दुनियाभर में होने वाली घटनाओं से खुद को परिचत कराएं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 9 मार्च को हुए दीक्षांत समारोह में गुजरात विवि के पूर्व कुलपति प्रो एम.एन. पटेल ने मेधावी छात्रों से यह आहवान किया। प्रोफेसर पटेल ने कहा कि दुनिया ऊपर से नीचे तक बदल सकती है, लेकिन मूल नैतिक मूल्य कभी नहीं बदलेंगे। ये मूल्य ईमानदारी, सच्चाई, स्वयं और दूसरे का सम्मान, कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत अखंडता और सामुदायिक भागीदारी हैं।

प्रोफेसर पटेल ने कहा कि वर्तमान में हम सभी की यह जिम्मेदारी है कि मूल नैतिक मूल्यों को पराजित न होने दें । प्रोफेसर पटेल ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे युवाओं को जीवन में सफलता के लिये कठोर एवं सतत परिश्रम से परिचित नहीं कराती। उन्होंने क्षमताओं पर संदेह न करने, कठिनाइयों से खतरा महसूस न करने और विश्वास न खोने की अपील की।

- विश्वविद्यालय के 9 मार्च को आयोजित हुए दीक्षांत समारोह में मेडल प्राप्त छात्र-छात्राओं के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा, मुख्य अतिथि गुजरात विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एम.एन. पटेल और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. तनेजा।

छात्रों के लिए विश्वविद्यालय से शुरू हो रोजगार परक कोर्स- प्रो. दिनेश शर्मा

परिसर संवाददाता

मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 दिनेश शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रोजगारपरक कोर्स शुरू होंगे। विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में अच्छा काम किया है। छात्रों के समस्त शैक्षिक प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा।

डॉ शर्मा ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में समस्त विवि में 70 फीसदी कोर्स समान हो जाएगा। 30 फीसदी कोर्स विवि अपने स्तर पर स्थानीय जरूरतों के अनुसार तैयार कर सकेंगे। प्रदेश के नए राजकीय महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस स्कीम में कोर्स चलेंगे जो सबंधित विवि चलाएंगे। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों के साथ एमओयू करने और विदेशी विवि के प्रदेश में जल्द कैंपस खोलने की बात कही।

लड़कियों की भागीदारी से बदल रहा समाज

डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अब समय बदल है। समारोह में 80 फीसदी लड़कियों ने मेडल पाए हैं, यानि न केवल समाज बदल रहा है बल्कि लड़कियां बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं।

-विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को उपहार भेंट किए गए (बाएं)। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और छात्र-छात्राएं (दाएं)।

-विश्वविद्यालय में संचालित हुए नए रोजगारपरक ,कौशल विकास एवं अन्य पाठ्यक्रमों हेतु नवनिर्मित भवन तथा अद्यतन सुविधायुक्त केन्द्रीय मूल्यांकन भवन।